



सुप्रीम कोर्ट से SDOP पूजा पांडे को राहत



सिवनी के बहुचर्चित हवाला डकैती कांड में मुख्य आरोपी और निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए राहत प्रदान की। इस फैसले के बाद प्रदेशभर में चर्चित यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

दरअसल, पूजा पांडे ने पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि याचिकाकर्ता 22 वर्षीय महिला हैं और एकल माता भी हैं। उनका दो से तीन वर्ष का बच्चा भी जेल में उनके साथ रह रहा है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी। पूरा मामला सिवनी जिले के खैरीटेक क्षेत्र में हुई कथित हवाला रकम की लूट से जुड़ा है।

काम को पहले समझें, टीम से बेहतर समन्वय करें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव



भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अनेकता में एकता ही हमारी ताकत है। हम योग्यता का सम्मान करना जानते हैं इसीलिए योग्यता के आधार पर सभी को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का उद्धरण दोहराते हुए कहा कि राजनीति और प्रशासन का एकमात्र ध्येय जनकल्याण होना चाहिए। राजनीतिक जीवन में

नैतिकता और शुचिता बेहद जरूरी है। हमें स्व. वाजपेयी के आदर्शों पर चल कर देश और प्रदेश की सेवा करनी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में प्रदेश के विभिन्न निगम, मंडल, बोर्ड, आयोग एवं प्राधिकरणों के नवनियुक्त पदाधिकारियों के उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, प्रदेश प्रभारी श्री महेंद्र सिंह, वरिष्ठ विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल तथा अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रो.

जनता के हित में नतीजे दें, संसाधनों का करें समुचित उपयोग

राजीव दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी निगम मंडलों के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि सेवा ही हमारा परम धर्म है। हमें परमेश्वर ने जनसेवा का अवसर दिया है इसीलिए सभी नवनियुक्त पदाधिकारी पूरी प्रशासनिक दक्षता, पूर्ण क्षमता, निष्ठा और सेवा भावना से काम करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आप सब सरकार का अभिन्न अंग हैं। आपके काम से ही सरकार की समाज और नागरिकों में साख बनेगी। इसीलिए पहले अपने काम को अच्छी तरह से समझें, विभागीय नीतियों और नियमों का समुचित अध्ययन करें। अपने उपलब्ध संसाधनों का उत्कृष्ट नियोजन करें और बेहतर तालमेल एवं सामंजस्य से अपने दायित्व का निर्वहन करें।

आय के नये स्रोत सृजित करें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए वित्तीय अनुशासन लाना, फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाना और नवाचारों से आय के नए स्रोत सृजित करना जरूरी है। नवनियुक्त पदाधिकारी संस्थान के अधिकारियों के साथ टीम भावना से काम करें और निगम मंडल में अनुशासन के लिये स्व-अनुशासन में रहें और नियमित मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में हम सबको नागरिकों की सेवा करते हुए प्रदेश को विकसित और भारत का सबसे बेहतर राज्य बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है।

17 लाख कमीशन लेते पकड़ा गया शिक्षा विभाग का अफसर

धार. इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने धार जिला शिक्षा केंद्र के डीपीसी प्रदीप कुमार खरे को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

आरोपी शौचालय निर्माण परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के बदले 17 लाख रुपये कमीशन मांग रहा था।

इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने जिला शिक्षा केंद्र धार के जिला परियोजना समन्वयक प्रदीप कुमार खरे को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई समग्र शिक्षा केंद्र कार्यालय में की गई, जहां आरोपी अधिकारी निर्माण कार्य के पूर्णता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के बदले रिश्वत ले रहा था।

लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, समग्र शिक्षा अभियान के तहत धार जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालय परिसरों में 122 शौचालयों का निर्माण कराया



जा रहा है। इस परियोजना के लिए करीब 3 करोड़ 42 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। शिकायतकर्ता दिलीप साधव, जो जिला शिक्षा केंद्र धार में प्रभारी सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ हैं, इस परियोजना की निगरानी कर रहे थे।

दिलीप साधव ने लोकायुक्त को शिकायत में बताया कि आरोपी प्रदीप कुमार खरे निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही पूर्णता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रहे थे। इसके एवज में आरोपी ने कुल परियोजना राशि का 5 प्रतिशत, यानी लगभग 17 लाख

रुपये कमीशन के रूप में मांगे थे। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने इंदौर लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय से शिकायत की। शिकायत के सत्यापन में आरोप सही पाए जाने पर लोकायुक्त की विशेष ट्रेप टीम गठित की गई।

योजना के तहत जैसे ही शिकायतकर्ता ने समग्र शिक्षा केंद्र कार्यालय में आरोपी डीपीसी प्रदीप कुमार खरे को रिश्वत की पहली किश्त के रूप में एक लाख रुपये दिए, वहां पहले से तैनात लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

ट्रेप दल में कार्यवाहक निरीक्षक सचिन पटेलिया, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक आशीष शुक्ला, आरक्षक विजय कुमार, कमलेश परिहार, मनीष माथुर, श्रीकृष्ण अहिरवार और प्रभात मोरे शामिल रहे।



इंदौर में पानी के लिए हा-हाकार

इंदौर में अब जलसंकट लगातार गहराता जा रहा है। शहर की पानी की टंकियां पूरी क्षमता से नहीं भर पा रही हैं, जिसके कारण कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो गई है।

स्थिति यह है कि पांच से छह मीटर क्षमता वाली टंकियां केवल दो से तीन मीटर तक ही भर रही हैं। इसका सीधा असर घरों तक पहुंचने वाले पानी पर पड़ रहा है और नलों में बेहद कम पानी आ रहा है। पानी की समस्या से परेशान होकर वीणा नगर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों का गुस्सा सोमवार सुबह सड़कों पर फूट पड़ा।

पानी नहीं मिलने से नाराज बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग खाली मटके और बर्तन लेकर सड़क पर उतर आए। लोगों ने पहले खाली मटके फोड़े और फिर सड़क पर बैठकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इलाके में न तो नियमित रूप से नलों में पानी आ रहा है और न ही टैंकों के जरिए पर्याप्त जल वितरण किया जा रहा है। कांग्रेस नेता अमित पटेल और पार्षद राजू भदौरिया के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं बस्ती से निकलकर सड़क पर बैठ गईं और वाहनों को रोकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

चक्काजाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारी 'महापौर पानी दो, पानी दो' के नारे लगाते रहे। रहवासियों ने आरोप लगाया कि वे पहले भी कई बार अधिकारियों से पानी की समस्या की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों का कहना था कि मजबूरी में उन्हें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा।

इसी बीच पांच नंबर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-41 में पहुंचे विधायक महेंद्र हार्दिया भी जलसंकट को लेकर नाराज नजर आए। कार्यक्रम में महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी मौजूद थे, लेकिन हालात देखकर विधायक बीच कार्यक्रम से ही लौट गए।

शिवपुरी: कोतवाली पुलिस ने सुलझाई नकबजनी की वारदात, दो शातिर चोर गिरफ्तार, 5 लाख का माल बरामद

शिवपुरी/अभि गोस्वामी की रिपोर्ट

कोतवाली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए माधव नगर में हुई एक बड़ी चोरी का पर्दाफाश किया है।

पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवरों, मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल किया गया ऑटो रिक्शा बरामद किया है। बरामद किए गए कुल मशरूका की कीमत करीब 5,00,000 (पांच लाख रुपये) बताई जा रही है।

यह था मामला

बीती 14 मई 2026 को फरियादी पूनम योगी (पत्नी अशोक योगी, उम्र 28 वर्ष, निवासी डाबर छिन्नी, हाल निवासी माधव नगर) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोरों ने उनके कमरे का ताला तोड़कर पलंग के अंदर बैग में रखे सोने-चांदी के जेवरों और तीन मोबाइल चोरी कर लिए हैं। शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 370/26 के तहत धारा 331(4) और 305(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज

कर जांच शुरू की थी।

ऐसे जाल में फंसे आरोपी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) यां गचेन डोलकर भू टिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले और नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) संजय चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना प्रभारी (TI) रोहित दुबे के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

20 से 25 सीसीटीवी खंगाले: टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे लगभग दो दर्जन सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए।

तकनीकी सहायता: सायबर सेल की मदद से संदिग्धों की लोकेशन और डेटा निकाला गया।

सटीक मुखबिरी: 17 मई 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि दो लोग पुराने रेलवे स्टेशन के पास पीले-हरे रंग के ऑटो



में बैठकर माधव नगर फतेहपुर से चोरी किया गया माल बेचने की फिराक में घूम रहे हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मौके से दोनों आरोपियों को दबोच लिया। शुरुआत में आरोपियों ने पुलिस को गोलमोल जवाब देकर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने 8 और 9 मई की दरमियानी रात चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी और उनका आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस गिरफ्तार में आए आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है:

अशोक उर्फ गोलू रजक (उम्र 25 वर्ष, निवासी आईटीआई फॉरेस्ट कॉलोनी, थाना देहात) - इसके खिलाफ पूर्व में अवैध शराब बिक्री के साथ-साथ हत्या (मर्डर) का मामला भी दर्ज है।

साहिल बाल्मीक (उम्र 22 वर्ष, निवासी 40 नंबर कोठी के पास, थाना देहात) - इसके खिलाफ भी पूर्व में अवैध शराब बेचने के मामले दर्ज हैं।

बरामद हुआ सामान

पुलिस ने आरोपियों के पास से शत-प्रतिशत चोरी का माल और वारदात में प्रयुक्त वाहन बरामद कर लिया है: जेवरों: एक बड़ा सोने का मंगलसूत्र,

सोने का बीजासेन, सोने के 10 मोती, सोने की नाक की नथ, एक सोने का 'ओम्', चांदी की करधनी और दो जोड़ी चांदी की पायल।

मो बाइल: एक सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल।

वाहन: वारदात में इस्तेमाल किया गया पीले-हरे रंग का ऑटो रिक्शा (रजिस्ट्रेशन नंबर: MP 33 JB 4132)।

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट बनने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है।

सराहनीय भूमिका

इस अंधे कत्ल और चोरी के खुलासे में कोतवाली थाना प्रभारी टीआई रोहित दुबे, उपनिरीक्षक (SI) सुमित शर्मा, सहायक उप निरीक्षक (ASI) प्रवीण त्रिवेदी, प्रधान आरक्षक गजेंद्र परिहार (374), विनय कुमार (570), जितेन्द्र रायपुरिया (489), अवतार सिंह (890), संतोष बैस (797), आरक्षक महेंद्र सिंह तोमर (528) और राहुल कुमार (285) की मुख्य और सराहनीय भूमिका रही।

कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ में राघवेंद्र जाटव को दी प्रदेश उपाध्यक्ष की कमान

दिव्यानंद अर्गल

भंड। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं संगठन प्रभारी महासचिव डॉ. कामले की सहमति से कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष नेहा पालीवाल द्वारा राघवेंद्र जाटव को मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी बेरोजगार प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।



पार्टी नेताओं ने उम्मीद जताई है कि राघवेंद्र जाटव संगठन को मजबूती देने के साथ-साथ युवाओं और बेरोजगारों की आवाज को मजबूती से उठाने का कार्य करेंगे। राघवेंद्र जाटव पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से

जुड़े हुए हैं और संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। वे लगातार कांग्रेस की नीतियों, जनहितकारी योजनाओं एवं पार्टी के संदेश को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। राघवेंद्र को पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। वहीं राघवेंद्र जाटव ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसका वे पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे तथा युवाओं और बेरोजगारों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का प्रयास करेंगे।

भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने पुनः बनाया देशराज धारिया को संभाग संयोजक

दिव्यानंद अर्गल

भंड। भीम आर्मी चीफ व सांसद चन्द्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाले संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा प्रदेश स्तर पर संगठन विस्तार और मजबूती को लेकर सभी संभागों के प्रभारियों की नियुक्ति की गई है।

इसी क्रम में देशराज धारिया को पुनः चंबल संभाग संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति भीम आर्मी भारत एकता

मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह तथा प्रदेश प्रभारी सुनील बैरसिया की अनुशंसा पर की गई। जारी नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि देशराज धारिया को संगठन के प्रति उनकी सक्रियता, समर्पण और कार्यशैली को देखते हुए पुनः चंबल संभाग संयोजक बनाया गया है। प्रदेश प्रभारी सुनील बैरसिया ने कहा कि देशराज धारिया अपने संभाग में प्रदेश सचिव एवं संभाग के मुख्य प्रभारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए संगठन निर्माण के कार्य को तेज गति देंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 10 दिनों के भीतर चंबल संभाग के

सभी जिलों का दौरा कर संगठन की समीक्षा की जाए तथा संबंधित जिला संयोजकों के नाम लिखित रूप में प्रदेश कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाए। संगठन पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि देशराज धारिया के नेतृत्व में चंबल संभाग में संगठन को नई मजबूती मिलेगी और सामाजिक न्याय तथा बहुजन समाज की आवाज को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा।



आप जनाधार से जुड़ें इसके तीन फायदे यानि शानदार जीत

ठोस तैयारी

हर मतदाता तक पहुंच और मजबूत रणनीति।

गहरा विश्लेषण

सही डेटा, सही समझ और सही निर्णय।

अच्छे परिणाम

अधिक जनसमर्थन और निश्चित जीत।

जनाधार

“चुनावी मैनेजमेंट सोल्यूशन पैकेज”

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें | **9827068888**

सहजयोग-चेतना के उत्कर्ष का पथ

जब मनुष्य संसार की निरंतर भागदौड़, तनाव और अस्थिरता के बीच स्वयं को खोने लगता है, तब उसके भीतर एक गहरी खोज जन्म लेती है — शांति की, सत्य की और अपनी वास्तविक पहचान की। यही खोज उसे आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। सहजयोग इसी



सूक्ष्म शरीर में सात प्रमुख चक्र स्थित होते हैं, जो चेतना के विभिन्न आयामों को नियंत्रित करते हैं। मूलाधार चक्र हमारी पवित्रता और स्थिरता का आधार है। स्वाधिष्ठान चक्र रचनात्मकता और सृजनशीलता का जागृत करता

है। नाभि चक्र संतोष और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। हृदय चक्र प्रेम, सुरक्षा और आत्मविश्वास का केंद्र है। विशुद्ध चक्र संवाद, सामूहिकता और मधुरता को विकसित करता है। आज्ञा चक्र क्षमा और अहंकार से मुक्ति का द्वार खोलता है, जबकि सहस्रार चक्र आत्मसाक्षात्कार और परम चेतना से जुड़ने का सर्वोच्च केंद्र माना जाता है। सहजयोग में जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर इन चक्रों को भेदते हुए सहस्रार तक पहुँचती है, तब व्यक्ति की चेतना का विस्तार होने लगता है। यह अनुभव केवल मानसिक नहीं, बल्कि गहराई से आत्मिक होता है। व्यक्ति अपने भीतर शांति की शीतल लहर, विचारों की निःशब्दता और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। जब हमारी चेतना शुद्ध और जागृत होती है, तब हम केवल स्वयं को नहीं, बल्कि पूरे संसार को अधिक प्रेम, शांति और एकत्व की दृष्टि से देखने लगते हैं। यही सहजयोग का सार है — आत्मा के प्रकाश को जागृत कर मानव चेतना को दिव्यता की ओर ले जाना। सहजयोग ध्यान पूर्णतः निःशुल्क है। सहजयोग की अधिक जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 से प्राप्त कर सकते हैं।

मानव शरीर के भीतर तीन मुख्य नाड़ियाँ बताई गई हैं — इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा नाड़ी हमारे भावनात्मक और भूतकाल से जुड़े पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। यह चंद्रमा की तरह शीतल और संवेदनशील ऊर्जा प्रदान करती है। पिंगला नाड़ी हमारी मानसिक और शारीरिक सक्रियता से जुड़ी होती है तथा भविष्य और कर्मप्रधान जीवन का प्रतीक मानी जाती है। इनके मध्य स्थित सुषुम्ना नाड़ी संतुलन और आध्यात्मिक उत्कर्ष का मार्ग है। जब मनुष्य का ध्यान सुषुम्ना में स्थिर होने लगता है, तब उसकी चेतना धीरे-धीरे उच्च अवस्था में प्रवेश करती है और वह भीतर की शांति का अनुभव करता है।

इंदौर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावडा ने सोशल मीडिया विभाग की नई टीम घोषित की पूजा. मंडोवरा को जिला संयोजक नियुक्त किया.



इंदौर. भारतीय जनता पार्टी इंदौर ग्रामीण में संगठन की मजबूती के लिए अहम नियुक्तियों की गई हैं। प्रदेश संगठन के निर्देशों और वरिष्ठ नेताओं की सहमति से जिले में सोशल मीडिया विभाग के जिला संयोजक के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंतखण्डेलवाल और प्रदेश संयोजक सुयश त्यागी की अनुमति के बाद जिला संगठन प्रभारी शैलेन्द्र डागा की सहमति से जिला अध्यक्ष श्रवण चावडा ने इन नई नियुक्तियों पर मुहर लगाई है। भाजपा द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार पूजा मंडोवरा को इंदौर जिला सोशल मीडिया संयोजक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला अध्यक्ष ने विश्वास जताया है कि नई टीम सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी की रीति-नीति और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाएगी।

चोइथराम फल सब्जी मंडी हुई हाईटेक

सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को बांटे गए 'वॉकी-टॉकी'

प्रकार खुशबू श्रीवास्तव

इंदौर। चोइथराम फल सब्जी मंडी प्रांगण की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, आधुनिक और हाईटेक बनाने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

मंडी परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल और त्वरित कार्रवाई के लिए आज विशेष रूप से 'वॉकी-टॉकी' सेट वितरित किए गए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मंडी प्रांगण में सुरक्षा के स्तर को बढ़ाना और किसी भी प्रकार की



आपातकालीन स्थिति या समस्या का तुरंत निदान करना है।

मुख्य बिंदु और लाभ:

हाईटेक सुरक्षा: वॉकी-टॉकी के उपयोग से मंडी प्रशासन और सुरक्षा अमला आधुनिक तकनीक से लैस होगा, जिससे निगरानी व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी।

त्वरित संवाद (Real-time Communication): परिसर के विशाल क्षेत्रफल को देखते हुए आपस में तुरंत संपर्क साधने के लिए यह तकनीक बेहद कारगर साबित होगी।

समस्याओं का त्वरित निदान: किसी भी संदिग्ध गतिविधि, चोरी, यातायात जाम या व्यापारियों और किसानों की समस्याओं की सूचना

तुरंत कंट्रोल रूम और साथी सुरक्षाकर्मियों तक पहुँचेगी, जिससे मौके पर ही त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी।

आपसी समन्वय: सभी सुरक्षाकर्मी और अधिकारी आपस में मिलकर एक मजबूत नेटवर्क की तरह काम करेंगे, जिससे मंडी में आने वाले किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके।

इस अवसर पर मंडी प्रशासन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ओ. पी. खेड़े के साथ साथ प्रमाण प्रभारी सोनकर जी, मुख्य सहायक श्री धर्मेन्द्र तोमर, सुरक्षा प्रभारी और सुरक्षाकर्मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

सनातन आस्था का उमड़ा सैलाब : करैरा में धूमधाम से निकली श्री जगन्नाथ मंदिर की भव्य ध्वज यात्रा



हेमंत भार्गव शिवपुरी जिला ब्यूरो

करैरा(शिवपुरी)। बाबा भानगिर महाराज की तपोभूमि एवं श्री बगीचा सरकार की पावन नगरी करैरा रविवार 17 मई को पूरी तरह भक्तिमय रंग में रंगी नजर आई, जब श्री जगन्नाथ मंदिर की भव्य ध्वज यात्रा श्रद्धा, उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ निकाली गई।

यात्रा श्री धूमेश्वर धाम के पीठाधीश परम पूज्य श्री श्री 1008 अनिरुद्धवन जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। ध्वज यात्रा का शुभारंभ कालीमाता मंदिर से वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूजा-अर्चना के साथ किया गया। जैसे ही यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों पर आगे बढ़ी, वैसे ही "जय जगन्नाथ" और धार्मिक जयघोषों से पूरा वातावरण गूंज उठा।

भजन-कीर्तन, ढोल-नगाड़ों और भक्तों की टोलियों ने यात्रा को भक्ति और आस्था



का अद्भुत स्वरूप प्रदान किया। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा एवं बच्चे शामिल हुए। श्रद्धालु हाथों में ध्वज लेकर भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। नगर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं एवं सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्पवर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जगह-जगह शीतल पेय और प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई। श्री जगन्नाथ मंदिर पहुँचकर ध्वज अर्पित किया गया तथा विशेष पूजा-अर्चना संपन्न हुई। आयोजन

के दौरान संत-महात्माओं ने अपने आशीर्वाचनों में सनातन संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और समाज में आध्यात्मिक चेतना बनाए रखने का संदेश दिया। इस भव्य आयोजन ने करैरा नगर के धार्मिक वातावरण को और अधिक भक्तिमय एवं उल्लासपूर्ण बना दिया। स्थानीय नागरिकों ने इसे सनातन धर्म की परंपराओं को सहेजने और नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ने वाला प्रेरणादायी आयोजन बताया।

किसानों को खरीफ फसलों की बुआई संबंधी नवीन वैज्ञानिक तकनीकी जानकारी प्रदान करेगा कृषि रथ

इन्दौर. मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष (कृषक कल्याण वर्ष) के रूप में मनाया जा रहा है।

इसी क्रम में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालयभोपाल के निर्देशानुसार कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा कृषि के माध्यम से किसानों तक नवीन वैज्ञानिक तकनीकों और कृषि संबंधी जानकारी पहुँचाने के उद्देश्य इस कृषि रथ का शुभारंभ किया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप

संचालक ने बताया कि किसानों को खरीफ फसलों की बुआई संबंधी जानकारी पहुँचाने के लिए जिले की विभिन्न विकासखण्डों में कृषि रथ का संचालन किया जा रहा है। इसी संबंध में इस तकनीकी रथ के माध्यम से कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं अन्य संबंधित विभागों के विषय विशेषज्ञ एवं कृषि वैज्ञानिक किसानों से सीधे संवाद स्थापित कर कृषि और संबंधित क्षेत्रों की उन्नत तकनीकों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से किसानों को ई-विकास प्रणाली के माध्यम से उर्वरक वितरण, खरीफ सीजन की

नवीन तकनीक, उन्नत किस्में, आधुनिक कृषि यंत्र, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, फल एवं सब्जी उत्पादन, फलोरीकल्चर, मत्स्य पालन तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु नई तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे आने वाले वर्षों में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। आज इंदौर जिले के चारों विकासखण्डों की 12 ग्राम पंचायतों - पिपल्दा, खण्डेल, शिवनी, हासलपुर, राजपुराकुटी, कुवाली, कुडाना, जामोदी, सिमरोड, धर्मट, पाडल्या एवं छड़ौदा में कृषि रथ द्वारा भ्रमण किया गया।

बेरडी में पंढरीनाथ मंदिर मार्ग विवाद-आक्रोश के बाद मंदिर समिति और ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

पांडुरना. मिनी पंढरपुर के नाम से विख्यात जिले के ग्राम बेरडी के ऐतिहासिक श्री पंढरीनाथ मंदिर मार्ग विवाद ने अब तुल पकड़ लिया है।

शनिवार को उपजे भारी आक्रोश के बाद, आज सोमवार को वारकरी संप्रदाय के श्रद्धालुओं, मंदिर समिति और हजारों ग्रामीणों ने सौसर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर अस्थायी समाधान की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान तहसील कार्यालय परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

**सुगम दर्शन के लिए
प्रतिवर्ष भूमि अधिग्रहण**

की मांग -

एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने मुख्य रूप से मांग की है कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अखंड हरिनाम सप्ताह के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा जाए। इसके लिए मंदिर के निर्गमन मार्ग से लेकर नरेंद्र चांडक की भूमि होते हुए बेरडी-लोधीखेड़ा मार्ग तक के 50 फीट चौड़े रास्ते का प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष अस्थायी रूप से अनिवार्य अधिग्रहण किया जाए, ताकि इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को आवाजाही में कोई असुविधा न हो।

तथा है पूरा मामला -

उल्लेखनीय है कि बेरडी



स्थित सौ वर्ष पुराने प्राचीन श्री पंढरीनाथ मंदिर के पश्चिम दिशा के मुख्य प्रवेश द्वार और वर्षों से उपयोग में लाए जा रहे मार्ग को बंद करने का प्रयास किया गया था। शनिवार की सुबह जैसे ही यह बात फैली, समूचे क्षेत्र के

श्रद्धालुओं की भावनाएं भड़क उठीं और उन्होंने मंदिर परिसर में इकट्ठा होकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल जमीन या रास्ते का विवाद नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र की आत्मा और लाखों हिंदुओं की धार्मिक

आस्था व सनातन परंपराओं से जुड़ा संवेदनशील मामला है।

पूर्व में मंदिर समिति ने की थी सौहार्दपूर्ण पहल -

ग्रामीणों के अनुसार, मंदिर समिति ने इस विवाद को टालने के लिए संबंधित भूमि स्वामियों से कई बार सौहार्दपूर्ण चर्चा की थी। जनहित को सर्वोपरि रखते हुए समिति ने उक्त भूमि को उचित मूल्य पर खरीदने या उसके बदले में दूसरी जगह उतनी ही भूमि देने की पेशकश भी की थी, ताकि विवाद का शांतिपूर्ण हल निकल सके। लेकिन इस बीच भूमि स्वामियों द्वारा मंदिर पक्ष के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की बात सामने आने के बाद श्रद्धालुओं का आक्रोश और अधिक गहरा गया।

हजारों की संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ -

आज सोमवार को सौसर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में न केवल बेरडी बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों से आए वारकरी संप्रदाय के भक्त, प्रबुद्ध नागरिक और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल थीं। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को बताया गया है कि यदि इस मार्ग को स्थाई रूप से सुरक्षित नहीं किया गया, तो प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठान (जिसमें लगभग चार लाख श्रद्धालु जुटते हैं) के समय कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए उचित वैधानिक कार्रवाई और जांच का आश्वासन दिया है।

इंदौर नगर निगम सहित नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी

इच्छुक नागरिक 25 मई तक आवेदन कर अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

इंदौर. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार इंदौर नगर निगम सहित नगरीय निकायों एवं पंचायतों के लिये फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी है।

तय कार्यक्रम के अनुसार इच्छुक नागरिक 25 मई 2026 तक निर्धारित केन्द्रों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने संबंधी आवेदन दे सकते हैं। साथ ही इस दौरान मतदाता सूची से नाम हटवाने एवं प्रविष्टि में संशोधन के संबंध में भी आवेदन दिए जा सकते हैं।

यह जानकारी आज यहां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दी गई। बैठक



में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीना मालवीय, जनपद अध्यक्ष श्री कान्हा पटेल, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नवजीवन विजय पवार, संयुक्त कलेक्टर एवं सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत श्रीवास्तव भी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि जिले के नगरीय निकायों एवं पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित नागरिक निर्धारित अवधि में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन अथवा विलोपन संबंधी दावे-आपत्तियां प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने बैठक में आयोग के निर्देशानुसार सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि जिले में पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इंदौर नगर निगम तथा नगर परिषद क्षेत्र में दावे-आपत्ति लेने के लिए प्रत्येक वार्ड के एक सुलभ मतदान केन्द्र में व्यवस्था की गई है। इसी तरह जिले के सभी ग्राम पंचायतों में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवम वर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुँचकर मतदाता सूची का अवलोकन करें। मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर अपने नाम जुड़वाए, प्रविष्टि में संशोधन होने पर भी आवेदन कर सुधार करवाये, मृत अथवा अन्यत्र चले गए मतदाताओं के नाम विलोपित करने के संबंध में भी आवेदन करें।

गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति, उपभोक्ताओं से बेहतर संवाद और राजस्व संग्रहण समय पर करें

समय सीमा बैठक में बिजली कंपनी के एमडी श्री सिंह ने कहा

इंदौर. उपभोक्ताओं को गुणवत्ता से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करे, उपभोक्ताओं, जनप्रतिनिधियों से बेहतर संवाद, समय पर राजस्व का संग्रहण को प्राथमिकता दें, इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उक्त निर्देश मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह ने दिए। सोमवार को समय सीमा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विभागाध्यक्ष गत वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व संग्रहण, विजिलेंस गतिविधियों, शिकायत निवारण, मीटरीकरण, उपभोक्ता सेवा संचालन, कार्य एवं परियोजना के कार्य के साथ ही सौंपे गए अन्य कार्यों को मैदानी अधिकारियों द्वारा समय पर करने



की रिपोर्ट तैयार कर सौंपे। इसी को आगामी पदस्थापना के समय आधार के रूप में स्वीकार किया जाएगा। श्री सिंह ने भंडार शाखा प्रभारी से बिजली सामग्री का स्टॉक मैटेन करने एवं मैटेनेंस प्रभारी से वर्षाकाल के पूर्व की तैयारी करने को कहा। श्री सिंह ने उपभोक्ताओं को मैटेनेंस की समय पर सूचना देने, उपभोक्ता एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद बेहतर करने एवं जारी देयकों की वसूली समय से करने को कहा।

इस दौरान मुख्य महाप्रबंधक श्री प्रकाश सिंह चौहान, कार्यपालक निदेशक श्री गजरा मेहता, मुख्य अभियंता श्री एसएल करवाड़िया, श्री आरसी जैन, श्री एसआर बमनके, श्री एसआर सेमिल, श्रीमती सुषमा गंगराडे, श्री एससी वर्मा, अतिरिक्त मुख्य महाप्रबंधक श्री संजय मालवीय, श्री अचल जैन, श्री सुनील पाटोदी, श्री पीएस चौहान, श्री अजयपाल सिंह अवास्या, श्री तरुण उपाध्याय आदि ने भी विचार रखे।



चापड़ा-उज्जैन-देवास से जुड़े उपभोक्ताओं को मिलेगी अधिक गुणवत्तापूर्ण बिजली

220 केवी सबस्टेशन चापड़ा में पुराने सिविल फाउंडेशन पर स्थापित किया गया कम क्षमता के स्थान पर अधिक क्षमता का कैपेसिटर बैंक

इंदौर. मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) के उज्जैन टेस्टिंग टीम के इंजीनियरों ने तकनीकी दक्षता और संसाधनों के बेहतर उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते 220 केवी सबस्टेशन चापड़ा में पुराने 5 एमवीएआर कैपेसिटर बैंक के सिविल फाउंडेशन पर ही नया 12 एमवीएआर क्षमता का कैपेसिटर बैंक सफलतापूर्वक स्थापित कर ऊर्जाकृत करने का एक

उल्लेखनीय कार्य किया है।

एमपी ट्रांसको उज्जैन के अधीक्षण अभियंता श्री अनिल सक्सेना ने बताया कि इस चौथे कैपेसिटर बैंक की स्थापना के बाद चापड़ा सबस्टेशन की कुल कैपेसिटर बैंक की क्षमता बढ़कर 48 एमवीएआर हो गई है, जिससे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।

कैपेसिटर बैंक से उपभोक्ताओं को मिलता है गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रवाह

सबस्टेशन में कैपेसिटर बैंक की स्थापना बिजली प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह सिस्टम में रिएक्टिव पावर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, जिससे पावर ट्रांसफार्मरों पर लोड कम होता है तथा पावर फैक्टर एवं वोल्टेज स्तर में सुधार होता है।

इसके परिणामस्वरूप विद्युत आपूर्ति अधिक स्थिर एवं गुणवत्तापूर्ण बनती है, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज और गुणवत्ता पूर्ण बिजली आपूर्ति के रूप में प्राप्त होता है।

इंदौर में प्रशासनिक कार्यप्रणाली में अभिनव पहल अब सोमवार की टीएल बैठक हुई वर्चुअली

इंदौर. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर दिए गए निर्देशों के पालन में इंदौर जिला प्रशासन ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में एक अभिनव पहल की है।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने प्रति सोमवार आयोजित होने वाली समय-सीमा पत्रों के निराकरण संबंधी टीएल बैठक को अब वर्चुअली माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में आज सोमवार को पहली बार टीएल बैठक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थित विभागों के अधिकारियों को छोड़कर

अन्य सभी विभागों के अधिकारी वर्चुअली रूप से शामिल हुए। बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित झाड़े, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर श्री नवजीवन विजय पवार, श्री रोशन राय, श्री रिकेश वैश्य भी शामिल रहे।



सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रशासन लगातार यह प्रयास कर रहा है कि लोगों की अनावश्यक आवाजाही कम हो, लेकिन प्रशासनिक कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव भी न पड़े। उन्होंने कहा कि आगे भी केवल अति आवश्यक विषयों पर ही अधिकारियों को भौतिक रूप से

बुलाया जाएगा। बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मिलावटखोरी विरोधी अभियान, फायर सेफ्टी एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। जिन विभागों में प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई, संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण प्राथमिकता से किया जाए। बैठक में राजस्व प्रकरणों की

समीक्षा भी की गई। नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन जैसे मामलों के समय-सीमा में निराकरण पर जोर देते हुए कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि विलंब के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ सीमांकन प्रकरणों में देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर पेनल्टी लगाई गई है तथा उसकी राशि प्रभावित आवेदकों को प्रदान की जाएगी। इसी तरह कलेक्टर श्री वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन के तहत लंबित पांच प्रकरणों के निराकरण की भी रैण्डम समीक्षा की। इसके अतिरिक्त हिट एंड रन प्रकरणों में लंबित रिपोर्टों को लेकर भी अधिकारियों को एक सप्ताह में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री वर्मा ने स्पष्ट किया कि जहां भी लापरवाही पाई जाएगी, वहां कठोर कार्रवाई की जाएगी।

आज से आरंभ हुआ “जन भागीदारी - सबसे दूर, सबसे पहले” अभियान

जनजातीय वर्ग के लिए 25 सेवाओं के “लाभार्थी संतुष्टि” शिविर होंगे आयोजित

इंदौर. जनजातीय वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 18 से 25 मई तक राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान “जन भागीदारी - सबसे दूर, सबसे पहले” अभियान संचालित किया जा रहा है।

जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने विभाग के सभी मैदानी अधिकारियों को सफलतापूर्वक शिविर लगाने एवं लक्षित समूह को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त सह संचालक जनजातीय क्षेत्रीय

विकास योजना डॉ. सतेन्द्र सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान जनजातीय समुदाय के हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना एवं धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों की सभी जनपद पंचायतों के चयनित ग्रामों में लाभार्थी संतुष्टि शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें योजनाओं से लाभान्वित भी किया जाएगा।

अभियान के तहत आयोजित शिविरों में 18 विभागों की कुल 25 सेवाओं का लाभ जनजातीय वर्ग के ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही यह

सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र हितग्राही अनुसार शासन की योजनाओं से वंचित न रहे। अभियान को सफल बनाने के लिये जिले के कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

शिविरों के आयोजन के लिये अपर संचालक श्रीमती रीता सिंह को राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी बनाया गया है। जबकि जिला स्तर पर संबंधित जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मध्यप्रदेश में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कुल 267 विकासखंडों के 11 हजार 377 ग्राम लाभान्वित होंगे। वहीं पीएम जनमन योजना के तहत कुल 122 विकासखंडों के 5 हजार 113 ग्राम लाभान्वित होंगे।

इंदौर में लगातार हो रहे अग्नि हादसे, लापरवाही पड़ रही भारी

इंदौर. इंदौर में लगातार आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। सुरक्षा मानकों में हो रही लापरवाही अब भारी पड़ रही है।

इस सप्ताह में ही आग लगने की चार बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। नगर निगम की टीमों समय समय पर सुरक्षा मानकों की जांच करती है लेकिन गोदाम मालिकों, फैक्ट्री संचालकों और इमारतों में हो रही लापरवाही की वजह से आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज ही खजराना थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर हादसे की खबर सामने आई है। यहां कर्बला मैदान के समीप स्थित एक टेंट हाउस के बड़े गोदाम में सोमवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। यहां पर भी न तो आग बुझाने के उपकरण थे न ही सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया।

यहां पर आग की लपटें इतनी तेज और भयानक थीं कि कुछ ही समय में आसमान में काले धुएं का एक विशाल गुबार छा गया, जो कई किलोमीटर दूर से ही साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। इस भयावह घटना को देखकर आसपास के इलाके के लोगों में दहशत और हड़कंप मच गया। स्थानीय नागरिकों द्वारा घटना की जानकारी तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना प्राप्त होते ही फायर ब्रिगेड की टीम बिना समय गंवाए तत्काल दुर्घटनास्थल पर पहुंची और बिना किसी देरी के आग पर काबू पाने की मशक्कत में जुट गई।

रुई गोदाम और फैक्ट्री में लगी आग

दो दिन पहले धार रोड स्थित प्लास्टिक दाना फैक्ट्री और सांवर रोड स्थित रुई गोदाम में शनिवार

सुबह भीषण आग लग गई। धार रोड पर आग इतनी विकराल थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियों के साथ पोकलेन मशीन और फायर फाइटिंग रोबोट की मदद लेनी पड़ी।

पेट्रोल डिपो के पास लगी आग

इसी महीने देवास नाके के पास मांगलिया में स्थित पेट्रोल डिपो के पास एक दुकान में भीषण आग लग गई। यहां पर भी आग बुझाने के उपकरण नहीं थे न ही आसपास पानी की व्यवस्था थी। फायर ब्रिगेड के आने तक आग आसपास की कई दुकानों में फैल गई। पास में ही पेट्रोल डिपो होने की वजह से तुरंत फायर ब्रिगेड एक्शन में आई और आसपास के सभी रास्तों को बंद करवाया गया। समय रहते यहां पर आग से काबू पाया गया।

इंदौर में प्रारंभ हुआ जनभागीदारी सप्ताह नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए लगेंगे संतुष्टि शिविर

इंदौर. जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से जनजातीय बहुल गांवों में 18 से 25 मई तक जनभागीदारी: सबसे दूर, सबसे पहले अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का आज शुभारंभ किया गया।

जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने और शासकीय योजनाओं का

शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के लिये “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत जिले में आज से 25 मई 2026 तक लाभार्थी संतुष्टि शिविर” आयोजित किये जायेंगे। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर श्री नवजीवन विजय पवार, श्री रिकेश वैश्य श्री रोशन राय उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं म.प्र. शासन के निर्देशानुसार जिले के जनजातीय समुदायों को शासन की

योजनाओं से शत-प्रतिशत लाभान्वित करने के लिये सभी विभिन्न विभागीय जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर पहुंच बनाते हुए सेवा संतुष्टि सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना तथा आजीविका से जुड़े अवसरों को प्रोत्साहित करना है।

इस अभियान की थीम “जनभागीदारी: सबसे दूर-सबसे पहले” रखी गई है। इस अभियान के तहत इंदौर जिले के चयनित 56 ग्रामों में स्थित आदि सेवा केन्द्रों में शिविर आयोजित कर जनजातीय क्षेत्रों

में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न विभागों के समन्वय से योजनाओं का लाभ दिया जायेगा।

सहायक आयुक्त एवं परियोजना अधिकारी, जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि इन शिविरों में एक ही स्थान पर आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जनधन खाता, राशन कार्ड, पी.एम. जीवन ज्योति बीमा योजना, पी.एम. किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, पी.एम. सुरक्षित मातृत्व अभियान, सिकल सेल मिशन, पी.एम. उज्ज्वला योजना, वनाधिकार पट्टा सहित अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया

जायेगा।

कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये 07 दिवसीय कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आज से जनभागीदारी सप्ताह का शुभारंभ कलेक्टर सभाकक्ष में उपस्थित जिला अधिकारी, विकास खंड और ग्राम स्तर के अधिकारियों के लिये अभिमुखीकरण कार्यक्रम से अभियान की शुरुआत की गई। महुँ परियोजना अधिकारी श्री मोहन सोनी द्वारा कलेक्टर सभाकक्ष में जनभागीदारी: सबसे दूर-सबसे पहले अभियान अंतर्गत साप्ताहिक कार्य योजना की विस्तृत जानकारी विभिन्न विभागों के सभी जिला अधिकारियों को प्रदान की गई।



दारू, दहेज और डीजे मुक्त विवाह के लिये चलेगा अभियान

इन्दौर. जनजाति अंचल में पनप रही कुरीतियों के खिलाफ एक अनोखी पहल देखने को मिली, जब बड़वानी में पुलिस अधीक्षक स्वयं विवाह समारोह में पहुंचे।

इस अवसर पर उन्होंने "3D" अर्थात दारू, दहेज और डीजे जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन का संकल्प दिलाया। यह विवाह केवल दो परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की मिसाल

बन गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी ने लोगों को यह संदेश दिया कि समाज सुधार केवल कानून से नहीं, बल्कि जनभागीदारी और जागरूकता से संभव है। समारोह में उपस्थित लोगों ने भी 3D मुक्त विवाह का समर्थन करते हुए सादगी और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया।

पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री पद्म विलोचन शुक्ल के नेतृत्व में विगत माह से जिला पुलिस बड़वानी द्वारा जिले में विवाह समारोह में दहेज, डीजे एवं दारू का उपयोग नहीं करने हेतु 3-डी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस विभाग की अभिनव पहल से प्रेरित होकर गत 4 मई को ग्राम धवली में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित

जनसंवाद में ग्राम जुनापानी के श्री रामा नरगावे द्वारा अपने तीनों बच्चों के विवाह समारोह में दहेज, डीजे एवं दारू का उपयोग नहीं करने का संकल्प लिया था। श्री रामा नरगावे द्वारा 17 मई को अपने पुत्र कृष्णा नरगावे, पुत्री रंजिता नरगावे एवं दिना नरगावे का विवाह समारोह बिना दहेज, डीजे एवं दारू के संपन्न किया गया। श्री रामा नरगावे द्वारा पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री पद्म विलोचन शुक्ल को अपने बच्चों के विवाह समारोह में आमंत्रित करने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम जुनापानी विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। उन्होंने दुल्हा-दुल्हनों को शुभकामना संदेश एवं उपहार देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। श्री शुक्ल ने नरगावे

दंपति को शॉल-श्रीफल देकर उनकी साहसिक पहल के लिये सम्मानित किया।

विवाह समारोह में सम्मिलित जनजातीय समाज के लोगो ने भी सालों से चली आ रही सभी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लिया। भविष्य में बिना दहेज, डीजे एवं दारू के विवाह समारोह सम्पन्न कराने तथा दहेज नहीं लेने व देने की कुरीति को पूर्ण रूप से बंद करने का संकल्प दिलाया गया। विवाह समारोह में थाना वरला का पुलिस स्टाफ तथा वन मंडल अधिकारी संधवा श्री इंद्रसिंह गडरिया एवं गायत्री परिवार के सदस्य श्री खुमसिंह तथा ग्राम सरपंच पटेल भी शामिल हुए।

पंचायत एवं नगरीय निकायों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिये प्रेक्षक नियुक्त

मतदाता सूची का 18 जून को होगा अंतिम प्रकाशन

भोपाल. पंचायतों एवं नगरीय निकायों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण के लिये प्रेक्षक नियुक्त किये गये हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जून को होगा।

आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया है कि जिला इंदौर के लिये श्री डी.पी. तिवारी, आगर-मालवा के लिये श्री कृष्ण मोहन गौतम, बैतूल के लिये श्री एस.पी. एस. सलूजा, मऊगंज के लिये श्री ए.के. सिंह, डिण्डोरी के लिये श्री शैलेन्द्र कियावत, शहडोल के लिये श्री नीरज दुबे, हरदा के लिये श्री

डी.डी. अग्रवाल, अनूपपुर के लिये श्री नरेन्द्र सिंह परमार, निवाड़ी के लिये डॉ. श्रीकांत पाण्डे, ग्वालियर के लिये श्री अरुण तोमर, सीधी के लिये श्री एस.एन. रूपला, नर्मदापुरम के लिये श्री निसार अहमद, रीवा के लिये श्री अरुण पाण्डे और रायसेन के लिये श्री शशि भूषण सिंह को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। ये सभी प्रेक्षक से.नि. भा.प्र.से. अधिकारी हैं।

इसी तरह राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री अनूप तिवारी को कटनी, श्री अनंत नारायण अरोड़ा को सतना, श्री प्रकाश व्यास को खरगोन, श्री राजा सिंह परिहार को शिवपुरी, श्री मदन सिंह ठाकुर को भिण्ड, श्री मदनलाल कौरव को देवास, श्री शरद कुमार श्रोत्रि को दमोह, श्री ए.आर.एन. गुप्ता को मेहर, श्री व्ही.के. चतुर्वेदी को सागर और श्री पी.के. वर्मा को नरसिंहपुर का प्रेक्षक तथा से.नि. अतिरिक्त सचिव जीएसटी श्री एस.डी. रिहारिया को दतिया जिले का प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।

मानसून पूर्व तैयारियों की कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने की समीक्षा

अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को दिए आवश्यक निर्देश

इन्दौर. कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए मानसून पूर्व तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में नगर निगम, पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित झाडे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर श्री नवजीवन विजय पवार, श्री रोशन राय, श्री रिकेश वैश्य भी शामिल रहे।

बैठक में कलेक्टर श्री शिवम



वर्मा ने मानसून पूर्व तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों के अनुरूप सभी विभाग तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री वर्मा ने नगर निगम को निर्देशित किया कि सभी नालों, चैनलों, तालाबों के आसपास तथा जलभराव वाले स्थलों की साफ-सफाई समय रहते पूरी कर ली जाए। साथ ही स्टॉर्म

वॉटर लाइन एवं ड्रेनेज सिस्टम की सफाई भी प्राथमिकता से की जाए, ताकि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति निर्मित न हो।

कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसा विहीन सड़कों एवं जलभराव संभावित स्थलों पर चेतावनी संकेतक लगाए जाएं तथा वहां कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। बैठक में एसडीआरएफ एवं होमगार्ड दलों को राहत एवं बचाव

कार्यों के लिए पूर्ण संसाधनों के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही वालंटियर्स की ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल एवं रेस्क्यू अभ्यास नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष चिन्हित किए गए जलभराव वाले स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा आवश्यकता अनुसार नए संवेदनशील स्थलों को भी चिन्हित किया जाए। उन्होंने बताया कि पूर्व में गठित विशेष टीमों भी इस वर्ष सक्रिय रहेंगी।

बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि वर्षा पूर्व सभी आवश्यक पैचवर्क, डामरीकरण एवं सड़क मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिए जाएं, ताकि बारिश के दौरान गड्ढों एवं जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। इन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग एवं फॉलोअप भी किया जाएगा।

बैठक में राहत स्थलों की समीक्षा भी की गई। निर्देश दिए गए कि आवश्यकता पड़ने पर राहत शिविर तत्काल प्रारंभ किए जा सकें, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं।

इसके अलावा पिकनिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखने, पुल-पुलियों पर संकेतक लगाने, बाढ़ की स्थिति में सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने, खदान एवं ईट भंडों में बैरिकेडिंग कराने तथा मानसून के दौरान विद्युत आपूर्ति सतत बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में पशुपालन विभाग को शिविर लगाकर पशुओं के टीकाकरण अभियान संचालित करने के निर्देश भी दिए गए।

ग्वालियर में भीषण आग, गोदाम धू-धू कर जला, जिम की मशीनें तक पिघलीं; बड़ा हादसा टला

ग्वालियर. ग्वालियर शहर के सागरताल क्षेत्र में एक कबाड़ और गाड़ियों की सीट बनाने वाले गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि इसकी तपन से पड़ोस में स्थित जिम की कुछ मशीनें तक पिघल गईं।

गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड ने समय रहते मोर्चा संभाला, वरना चंद कदमों की दूरी पर स्थित पेट्रोल पंप और मैरिज गार्डन बड़ी तबाही का कारण बन

सकते थे। दमकल की 15 गाड़ियों ने लगातार पानी की बौछार कर आग को शांत किया।

गोदाम में गाड़ियों की सीट बनाने के लिए भारी मात्रा में फोम और कबाड़ भरा था, जिसने आग को चंद मिनटों में विकराल बना दिया। आसपास आग से अफरातफरी मच गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, साथ ही दमकल दस्ते को भी सूचना दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और तत्काल आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पास की जिम की मशीनें और

उपकरण गर्मी से खराब हो गए। लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए।

सूचना मिलते ही पुरानी छावनी और फायर मुख्यालय से दमकल की गाड़ियां पहुंचीं। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालकर आसपास के मकानों को खाली कराया। हादसा स्थल से महज दो-तीन मकान छोड़कर ही एक पेट्रोल पंप और पास में ही रजवाड़ा मैरिज गार्डन स्थित है। अगर हवा का रुख थोड़ा भी बदलता या आग पर काबू पाने में देरी होती, तो ग्वालियर में बड़ा विस्फोट या जनहानि हो सकती थी।



बिजली बिलों की वसूली की शुरुआत बड़े लोगों से करें : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

भोपाल. बकाया बिजली बिलों की वसूली की शुरुआत बड़े लोगों से करें। यह कार्यवाही दिखनी भी चाहिए। इसके सकारात्मक प्रभाव होंगे।

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश सोमवार को मंत्रालय में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से ई-स्कूटी से वल्लभ भवन पहुंचे।

स्मार्ट मीटर लगाने के बाद कितना सुधार हुआ

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने पूछा कि जिन क्षेत्रों में शत-प्रतिशत स्मार्ट मीटर लग गये हैं, उनमें बिलिंग, वासूली एवं हानियों में कितना सुधार आया है। उन्होंने कहा कि इसकी गहन समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। क्षेत्र में कुल 17 लाख 66 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के पहले पुराने मीटर के सभी लंबित देयकों का बिल जारी करें।

स्मार्ट मीटर लगाने के बाद

नये बिल जारी करें। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि जो सीई और एसई फील्ड में नहीं जाते, उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि अवैध अविद्युतीकृत कालोनियों के विद्युतीकरण के लिये सुनियोजित कार्य योजना बनायें।

विगत 6 माह में हुई ट्रिपिंग की समीक्षा करें

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि विगत 6 माह की ट्रिपिंग की समीक्षा करें। जरूरत के अनुसार कवर कंडक्टर डालें, जिससे ट्रिपिंग कम हो। मेटेनेस के पूर्व और पश्चचात की समीक्षा देखें, ट्रिपिंग में कितना आया। कॉल सेंटर में प्राप्त शिकायतों के निराकरण की औसत समय-सीमा कम करें। ओवर लोडेड ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के लिये योजना बनाकर कार्य करें। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने आरडीएसएस के कार्यों की भी समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिये।

बैठक में सचिव ऊर्जा श्री विशेष गढ़पाले, एमडी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी श्री अजय गुप्ता उपस्थित थे। बैठक में सभी क्षेत्रीय अधिकारी वचुअली शामिल हुए।

आजीविका मिशन अंतर्गत योजनाओं का वित्तीय प्रबंधन करें बेहतर : मंत्री श्री पटेल

संविदा कर्मियों के लिए समान कार्य-समान वेतन का हो निर्धारण, पदों का करे युक्तियुक्तकरण

राज्य आजीविका मिशन फोरम की शासी निकाय की बैठक में मंत्री श्री पटेल ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश



भोपाल. पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन फोरम की शासी निकाय की बैठक ली और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में विगत बैठक के निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री पटेल ने आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के एचआर मैनुअल पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का निर्धारण किया जाए

और आवश्यकतानुसार पदों का युक्तियुक्तकरण भी किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने योजनाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की बात कही, जिससे क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध रहे और विभाग की देयताएं (लायबिलिटी) कम हो सकें।

बैठक में मंत्री श्री पटेल ने जनोपयोगी सुविधाओं के लिए वन भूमि के उपयोग की अनुमति देने वाले नए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप एफआरए लैंड डायवर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पारदर्शी, सुगम और त्वरित प्रक्रिया से वन भूमि पर रहने वाले अनुसूचित जनजाति के कृषकों और मजदूरों को बड़ी सुगमता

होगी। इसके साथ ही, प्रदेश के 52 जिलों में स्थापित 85 आजीविका पुस्तकालयों की समीक्षा करते हुए उन्होंने इन केंद्रों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्किल ट्रेनिंग देने पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा और अन्य आवश्यक कौशलों में प्रशिक्षित करने के लिए केंद्रीकृत वीसी के माध्यम से प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री पटेल ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 के तहत वर्तमान बाजार की मांग के अनुसार स्किल्स की पहचान करने और स्किल गैप एनालिसिस के आधार पर ही नवीन परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए नई टेंडर प्रक्रिया

की सफलता की कहानियों को बुकलेट, फ्लेक्स और फिल्मों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित करने को कहा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एमपीएसईडीसी के माध्यम से फंड फ्लो की डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए बनाए जा रहे पोर्टल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए त्वरित कार्य करें। 5 हेक्टेयर से ऊपर के तालाबों की सूची तैयार करें और आवश्यकता के आधार पर अधूरे कार्यों को पूरा करें। 1 जुलाई से विकसित भारत - जी-राम-जी के तहत सभी निर्माण कार्य होने हैं इसलिए पूर्व से कार्य योजना तैयार रखें। इसमें विस्थापन के कारण शिफ्ट हुए परिवारों का विशेष ध्यान रखें और उन्हें इस योजना का लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश में डिजिटल सुशासन का आधार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क

सुरक्षित, तीव्र, स्वचालित और स्केलेबल प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाएगा विकसित-डिजिटल इंडिया मिशन को राज्य में मिलेगी नई गति

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को सशक्त एवं नागरिक केन्द्रित बनाने की दिशा में लगातार प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं।

व्यवस्था में पारदर्शिता, त्वरित सेवा प्रदाय एवं तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार डिजिटल अधोसंरचना को सशक्त कर रही है। मंत्रि-परिषद द्वारा इसलिये प्रदेश में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) योजना के संचालन एवं विस्तार को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए 526 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का क्रियान्वयन म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

स्वान : सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की महत्वपूर्ण डिजिटल अधोसंरचना

स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की महत्वपूर्ण डिजिटल अधोसंरचना है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत की गई थी। मध्यप्रदेश में वर्ष 2006-07 में इस योजना की शुरुआत राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर के शासकीय कार्यालयों को एकीकृत डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने के उद्देश्य से की गई।

एमपी स्वान से भोपाल स्थित मुख्य नेटवर्क केंद्र से प्रदेश के सभी जिलों एवं विकासखण्ड मुख्यालयों को एमपीएलएस तकनीक द्वारा जोड़ा गया है। यह नेटवर्क डेटा, वॉयस एवं वीडियो संचार की सुरक्षित एवं विश्वसनीय सुविधा उपलब्ध कराता है, जिससे शासन की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का संचालन सुचारु रूप से हो रहा है।

अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिक केंद्रित डिजिटल व्यवस्था

एमपी स्वान आज प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की

रीढ़ के रूप में कार्य कर रहा है। इससे विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकीकृत नेटवर्क प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिससे शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिक केंद्रित बनी है। वर्तमान में लगभग 10 हजार से अधिक शासकीय कार्यालयों को एमपीएलएस, आरएफ, ओएफसी एवं एलएएन तकनीकों से जोड़ा गया है और 99 प्रतिशत से अधिक नेटवर्क अपटाइम सुनिश्चित किया गया है।

संपदा 2.0, सीसीटीएनएस, ई-कोर्ट, आरसीएमएस, आधार एवं ट्रेजरी जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का संचालन इसी नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है। स्वान तकनीक के क्रियान्वयन से नेटवर्क प्रबंधन अधिक सक्षम हुआ है। प्रमुख शहरों में 1 जीबीपीएस तक की उच्च गति कनेक्टिविटी स्थापित की गई है। साथ ही बैंडविड्थ लागत में लगभग 50 प्रतिशत की कमी प्राप्त हुई है।

विभिन्न विभागों में डिजिटल सेवाओं को

मिली गति

एमपी स्वान नेटवर्क से राजस्व विभाग में भू-अभिलेख, नामांतरण, नक्शा एवं ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं, गृह विभाग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित कानून-व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन, शिक्षा विभाग में ऑनलाइन परीक्षा एवं छात्रवृत्ति को गति मिली है। साथ ही वित्त विभाग में आईएफएमएस आधारित बजट एवं पेंशन प्रबंधन को सशक्त बनाया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और सामान्य प्रशासन विभाग में ई-ऑफिस एवं डिजिटल फाइल ट्रेकिंग प्रणाली से शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी बनी है।

सायबर सुरक्षा के साथ आधुनिक निगरानी और नियंत्रण प्रणाली

नेटवर्क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पेरिमीटर यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट आधारित सुरक्षा प्रणाली लागू की गई है। इससे आवश्यक एवं जावक नेटवर्क

की सतत निगरानी एवं नियंत्रण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे सायबर खतरों से सुरक्षा प्राप्त हो रही है। साथ ही डिजास्टर रिकवरी साइट की स्थापना की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिससे आकस्मिक परिस्थितियों में भी शासकीय सेवाओं का त्वरित पुनर्संचालन संभव हो सकेगा।

भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हाई-स्पीड बैकबोन नेटवर्क, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क आर्किटेक्चर एवं नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल जैसी उन्नत तकनीकों से नेटवर्क को और अधिक सुरक्षित एवं आधुनिक बनाया जाएगा।

डिजिटल इंडिया मिशन को नई गति

एमपी स्वान ने प्रदेश में डिजिटल सुशासन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना की निरंतरता के माध्यम से इसे एकाधिक सुरक्षित, तीव्र, स्वचालित और स्केलेबल नेटवर्क प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जाएगा।

इससे आने वाले वर्षों में डिजिटल सेवाओं का और अधिक विस्तार होगा तथा "डिजिटल इंडिया" मिशन को राज्य स्तर पर नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. दवे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मां नर्मदा के अनन्य उपासक, पर्यावरणविद एवं प्रखर चिंतक, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. अनिल माधव दवे की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नदियों की अविरोधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनका समर्पण सदैव अनुकरणीय रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से केंद्रीय मंत्री तक का उनका सफर सादगी, राष्ट्रसेवा और कर्तव्यनिष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण है।

चिकित्सा व्यवसाय नहीं, मानव सेवा का है माध्यम - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

स्वास्थ्य विभाग एवं सेवांकुर भारत प्रकल्प के बीच हुआ एम.ओ.यू.

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मरीज की चिकित्सा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, यह मानव सेवा का एक माध्यम है। हमें ऐसे चिकित्सक तैयार करने हैं, जो मानव सेवा और मरीज की सेवा के लिये तत्पर हों।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में आयोजित एक समझौता ज्ञापन बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल की उपस्थिति में राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग तथा सेवांकुर भारत, डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान, छत्रपति संभाजी नगर (महाराष्ट्र) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर आदान-प्रदान किया गया। एमओयू की अवधि 5

वर्ष की है। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश को सेवा-प्रधान स्वास्थ्य नेतृत्व का मॉडल राज्य बनाना है। एमओयू का मुख्य लक्ष्य सेवा-प्रधान डॉक्टरों की ऐसी पीढ़ी तैयार करना है, जो व्यवसायिक ही नहीं, समाज में परिवर्तन के वाहक भी बनें। यह एमओयू अनुभव-आधारित शिक्षण व

मूल्य-आधारित नेतृत्व विकास अर्थात् सेवा के जरिये सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें "एक सप्ताह देश के नाम" कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, जिसमें लगभग



300 प्रतिभागियों को छत्रपति संभाजीनगर में गहन प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के बाद निरंतर सहभागिता के लिए अनुभव साझा सत्र एवं व्यक्तिगत

विकास शिविर भी आयोजित किये जायें। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल सहित सेवांकुर भारत प्रकल्प के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान की स्थापना वर्ष 1989 में समाज के प्रति समर्पित चिकित्सकों द्वारा की गई थी। विगत तीन दशकों में संस्था ने 70 लाख से अधिक वंचित एवं जरूरतमंद रोगियों को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं

करुणामय चिकित्सा सेवा प्रदान की है। संस्था का केंद्र बिंदु डॉ. हेडगेवार रुग्णालय, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) है, जो सेवाभाव, सादगी एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता के साथ आम जन तक उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिये प्रतिबद्ध है। वर्तमान में प्रतिष्ठान देशभर में 46 एकीकृत परियोजनाओं का संचालन कर रहा है, जिनमें संभाजीनगर, नासिक एवं शिवसागर (असम) के बहु-विशेषज्ञता अस्पताल, चिकित्सा, नर्सिंग एवं फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, एशिया का अग्रणी अत्याधुनिक रक्तपेढी; तथा झुग्गी बस्ती एवं ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजनाएँ सम्मिलित हैं। हृदय शल्य चिकित्सा, आईवीएफ, नवजात शिशु देखभाल, एमआरआई एवं कैथ लैब जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ-साथ संस्था महिला एवं बाल विकास, टीकाकरण अभियान और जन स्वास्थ्य जागरूकता जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय है।

हत्या या आत्महत्या



इंदौर | 3 मई 2026 की रात एमआईजी थाना क्षेत्र में हुई अमित यादव की मौत को लेकर परिवारजन ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

परिजनों का कहना है कि अमित यादव को पंकी वर्मा ने

अपने घर बुलाया था, जिसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या या आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए

हैं। उनका कहना है कि जब वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने पहुंचे तो उनसे लिखित में यह देने को कहा गया कि अमित यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। परिवारजन ने इस पर आपत्ति जताते हुए निष्पक्ष जांच और पंकी वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

विद्यार्थियों को रेडक्रॉस के सिद्धांतों से करें संस्कारित: राज्यपाल श्री पटेल

जूनियर और युवक रेडक्रॉस शाखा की समीक्षा बैठक में हुए शामिल

राज्यपाल श्री पटेल ने अपने कारकेड को किया आधा



भोपाल. राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि रेडक्रॉस के सिद्धांत बच्चों में सेवा, सद्भाव, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करते हैं। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। उनका सर्वांगीण विकास कर, उन्हें आदर्श नागरिक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए सक्षम पीढ़ी के निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों में रेडक्रॉस की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सभी शिक्षण संस्थानों को हर विद्यार्थी को रेडक्रॉस से जोड़ने की जिम्मेदारी उठाना चाहिए।

राज्यपाल श्री पटेल सोमवार को रेडक्रॉस की मध्यप्रदेश राज्य शाखा इकाई द्वारा आयोजित जूनियर रेडक्रॉस एवं युवक रेडक्रॉस शाखा की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक का

आयोजन होटल पलाश रेसीडेंसी में किया गया। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल श्री पटेल ने ईंधन बचत के दृष्टिगत अपने कारकेड के वाहनों की संख्या को आधा कर दिया है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान, बच्चों में ज्ञान और संस्कार को प्रदान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। संस्थानों को विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। उन्हें समसामयिक चुनौतियों और जीवन की प्रतिस्पर्धाओं के लिए जुझारू बनाएं। सफलताओं के दबाव और तनाव प्रबंधन से निपटने का हुनर सिखाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत

के संकल्प को साकार करने में बच्चों और युवाओं का विशेष योगदान रहेगा। ऐसे में विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ना होगा। कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। आदर्श नागरिक बनाकर मानवता के ध्वजवाहक के रूप में तैयार करना होगा। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान, प्रदेश और जिला रेडक्रॉस इकाईयों के साथ सक्रिय समन्वय करें। रेडक्रॉस की वार्षिक गतिविधियों का कैलेंडर अनुसार नियमित आयोजन करें। उन्होंने देश के अन्य राज्यों में रेडक्रॉस के नवाचारों का अध्ययन कर प्रदेश की परिस्थिति के अनुरूप समावेश करने की बात कही।

इंदौर के खजराना क्षेत्र में पांच गोदाम जले

इंदौर. इंदौर के खजराना क्षेत्र के पटेल नगर में एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देता रहा। इस हादसे में पांच गोदाम आग की भेंट चढ़ गए और करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया।

जिस बस्ती में ये गोदाम स्थित थे, उसके आसपास घनी आबादी होने के कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचीं और करीब चार

घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लोकेश सोनी के गोदाम में टेंट का सामान, कपड़े और प्लास्टिक की डेकोरेशन सामग्री रखी हुई थी।

इसी वजह से आग तेजी से फैल गई और आसपास के गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग बुझाने में पचास से ज्यादा टैंकर पानी का इस्तेमाल किया गया।